# BSNL EMPLOYEES UNION

**Recognised Union in BSNL**

(Registered Under Indian Trade Union Act 1926. Regn.No.4896)

CHQ:Dada Ghosh Bhawan, Opp. Shadipur Bus Depot., New Delhi – 110008

Email: chqbsnleu@sify.com, website: bsnleuchq.com

P. Abhimanyu
General Secretary

Phone: (O) 011-25705385
Fax : 011-25894862


**बीएसएनएलईयू/102 (सर्कुलर नं. 01)** **दिनांक 4 जनवरी, 2012**

सेवा मे

प्रिय साथी,

### सी एच क्यू की नव वर्ष 2012 के लिए शुभकामनाएं

सी एच क्यू आप सभी को नव वर्ष 2012 के लिए शुभकामनाएं पेश करता है। 2011 मे, बी एस एन एल को बचाने के लिए भारी संघर्ष चलाए गए हैं। उसी तरह बी एस एन एल की सेवाओ को सुधारने के लिए भी "उपभोक्ता रुचि वर्ष" मनाने का अभियान चलाया गया है। ये प्रयत्न वर्ष 2012 में भी जारी रहने चाहिएं। हम सभी को वर्ष 2012 में बी एस एन एल को एक जीवंत और लाभकारी पी एस यू बनाने के लिए समर्पित रहना चाहिए।

### 15 दिसंबर 2011 की हड़ताल

15 दिसंबर 20111 की एक दिवसीय हड़ताल शानदार तरीके से सफल रही। कुछ लोगो की हड़ताल पर जाने के बारे में कर्मचारियों की तैयारी के बारे में आशंकाओं के बावजूद नॉन-एक्जीक्यूटिवों और एक्जीक्यूटिवो ने हड़ताल को पूरी तरह सफल बना कर फिर एक बार इतिहास रचा है। नॉन-आप्टेड अधिकारियो को कार्यालयों में प्रवेश करने से रोकने के निर्णय ने संघर्ष को गति प्रदान की है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एफ एन टी ओ इस हड़ताल मे शामिल नहीं हुई और इसके खिलाफ जोर-शोर से अभियान चलाया। हमें गर्व है कि बी एस एन एल ई यू ने हड़ताल आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर्किल और जिला सचिवों से अनुरोध है कि वे अपनी अपनी एक्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंगे आयोजित करें और हड़ताल की मजबूतियों और कमजोरियों की समीक्षा करें ताकि भावी संघर्षों को और असरदार बनाया जा सके।

### महत्वपूर्ण प्रगति

जे ए सी के बैनर तले हमारी यूनियनो और एसोसिएशनों द्वारा किए गए लगातार प्रयत्नों के कारण बी एस एन एल को मजबूत करने के संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हम यह मांग करते रहे है कि बी एस एन एल द्वारा गैर-मानक बी डब्ल्यू स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने के लिए डॉट द्वारा बी एस एन एल को धन रिफंड करना चाहिए। डॉट ने इसे स्वीकार कर लिया है और बी एस एन एल को धन शीघ्र वापस किया जाएगा। उसी प्रकार बी एस एन एल के पेंशन अंशदान के बारे में उठाई गई मांग भी हल हो गई है। हल यह हुआ है कि बी एस एन एल मूल वेतन के आधार पर पेंशन अंशदान का भुगतान करेगी न कि अधिकतम वेतनमान पर। तीसरा मुद्दा निजी कंपनियों द्वारा सर्किलों मे जहां उनके पास लाइसेस नहीं है 3 जी सेवाएं प्रदान करने का है। हमने यह जोरदार मांग की थी कि 3 जी सेवाओ के लिए निजी कंपनियों के अंतः सर्किल रोमिंग समझौते को रद्द किया जाए। यह 15 दिसबर 2011 की हड़ताल की एक प्रमुख मांग है। डॉट ने 23-12-2011 को अंतः सर्किल रोमिंग समझौतो को रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। (निजी कंपनियों ने अब इस मुद्दे को टी डी एस ए टी के पास उठाया है।)

### नई दिल्ली में बिल्डिंग खरीदने का काम पूरा हुआ

तिरुवनंतपुरम ए आई सी के फैसले के अनुरूप सी एच क्यू ने हमारी यूनियन के लिए वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली में एक बिल्डिंग खरीदी है। बिल्डिंग की कीमत 2 करोड़ 90 लाख रुपये है। अतिम भुगतान 08-12-2011 को कर दिया गया है और उसी दिन बिल्डिंग पर कब्जा ले लिया गया है। इसके अलावा 27-12-2011 को बिल्डिंग का पंजीकरण "के जी बोस मेमोरियल

ट्रस्ट'' के नाम करा लिया गया है। इस बीच सी एच क्यू के 'बिल्डिंग फंड' के आह्वान को हमारे कामरेडों से पर्याप्त रेस्पांस नहीं मिला है। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सी एच क्यू ने इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए बैंक से एक करोड़ चालीस लाख रुपये का कर्ज लिया है। यह कर्ज अदा करना है। अतः सर्किल और जिला सचिवों से अनुरोध है कि वे बिल्डिंग फंड एकत्रित करने में तेजी लाएं।

**उपभोक्ता रुचि वर्ष अधिक जोरदार तरीके से चलाओ**

उपभोक्ता रुचि वर्ष जिसका जे ए सी ने आह्वान किया है, उसने निस्संदेह अच्छे परिणाम दिए हैं। इस कार्यक्रम को और जोरदार तरीके से चलाने की जरूरत है। हमारे प्रयत्नों के फलस्वरूप सामग्री, उपकरण, मोडेम आदि आने शुरू हो गए हैं। इन चीजों की उपलब्धता के बारे में फील्ड स्तर से फीडबैक भी जरुरी है। सर्किल और जिला सचिवों से अनुरोध है कि वे उपभोक्ता रुचि वर्ष मनाने में कोई कमी न आने दें। उनसे अनुरोध है कि वे फील्ड स्तर के साथियो से संपर्क करें, उनका आवश्यक उत्साहवर्धन करें और 'उपभोक्त रुचि वर्ष' को मनाने की मॉनीटरिंग भी करें।

**28-02-2012 को एक दिवसीय हड़ताल आयोजित करने की तैयारियां शुरु करें**

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों जैसे बी एम एस, इंटक, एटक, एच एम एस, सीटू आदि ने 28-02-2012 को एक दिवसीय हड़ताल करने का आह्वान किया है। मूल रूप से हड़ताल यू पी ए सरकार की जन-विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ है। हड़ताल की विशेष मांगों को पहले ही सी एच क्यू की वेबसाइट पर रखा गया है और टेलीक्रूसेडर के जनवरी अंक में भी छापा गया है। मांगें जैसे कोई विनिवेश नहीं, बोनस भुगतान से सभी सीमाओं को हटाया जाए, सभी के लिए सुनिश्चित पेंशन और स्थाई प्रकृति के काम का कोई ठेकेदारीकरण नहीं, प्रत्यक्ष रूप से बी एस एन एल और उसके कर्मचारियों से जुड़ी हैं। बी एस एन एल की यूनियनें और एसोसिएशनें बी एस एन एल की सरकार की, गलत नीतियों से रक्षा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। हमें यह समझना चाहिए कि यह पर्याप्त नहीं है। हमें आशंका है कि सरकार बी एस एन एल में, भविष्य में इसका निजीकरण करने के लिए ही, वी आर एस लाने की कोशिश कर रही है। अगर सरकार की जन-विरोधी और मजदूर-विरोधी नीतियों पर रोक नहीं लगाई जाती तो हम बी एस एन एल की रक्षा नहीं कर सकते। इसे हासिल करने के लिए हमें 28 फरवरी की हड़ताल में शामिल होना चाहिए जब पूरा मजदूर वर्ग सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने जा रहा है।

**खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत एफ डी आई–यू पी ए सरकार ने पीछे कदम हटाया**

यू पी ए सरकार को हाल ही में उस समय जोर का झटका लगा जब उसे खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत एफ डी आई की इजाजत देने के अपने कैबिनेट के निर्णय को स्थगित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। सरकार के निर्णय को जनता के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। देश के तमाम खुदरा व्यापारियों ने 01-12-2011 को एक शानदार ''व्यापार बंद'' का आयोजन किया। बी एस एन एल ई यू ने भी उस दिन देशभर में व्यापक प्रदर्शनों का आह्वान किया। जनता के अभूतपूर्व विरोध को देखते हुए कुछ यूपीए घटकों को भी कैबिनेट के निर्णय का विरोध करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसने सरकार को तुरंत पीछे कदम हटाने के लिए बाध्य किया। यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि जनता सरकार की जन-विरोधी नीतियो को कैसे रोक सकती है।

**बी एस एन एल ई यू की नए मान्यता नियमों की मांग**

जयपुर में हुई केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी मीटिंग में बी एस एन एल से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर नए मान्यता नियम बनाने की मांग करने का निर्णय लिया गया है। इसी के अनुरूप सी एच क्यू ने बी एस एन एल प्रबंधन को अगले सदस्यता सत्यापन से पहले नए मान्यता नियम बनाने के लिए पत्र लिखा है।

**बी एस एन एल बोर्ड ने एन ई 12 वेतनमान को स्वीकृति दी**

लगातार मान-मनोती के बाद बी एस एन एल बोर्ड ने 23-12-2011 को एन ई 12 वेतन मान (16390-33830) को स्वीकृति दे दी है। इससे पहले बी एस एन एल प्रबंधन कमेटी ने इस वेतनमान को स्वीकृति दे दी थी। अब इस वेतनमान को स्वीकृति के लिए डॉट के पास भेजा जाएगा। सी एच क्यू यह देखने के सभी प्रयत्न कर रहा है कि वेतनमान को डॉट द्वारा बिना देरी किए स्वीकृति दे दी जाए ताकि इसे शीघ्र लागू किया जा सके।

**नेशनल काउंसिल मीटिंग आयोजित करने में असामान्य देरी**

नेशनल काउसिल की 26वीं मीटिंग मे असामान्य देरी की गई है। यह सितंबर/अक्टूबर 2011 में आयोजित की जानी चाहिए थी। आई टी एस अधिकारियो की वापसी देरी का एक मुख्य कारण है। इसके बावजूद सीएचक्यू मीटिग जनवरी 2012 मे आयोजित करने की कोशिश कर रही है।

**पी एफ आर डी ए विधेयक शीतकालीन सत्र में नहीं रखा गया**

यह समाचार प्राप्त करके कि पी एफ आर डी ए विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र मे विचार हेतु लाया जा सकता है पी एफ आर डी ए विधेयक के खिलाफ संचालन समिति ने 22-12-2011 को लंच आवर में प्रदर्शनों का आह्वान किया। किंतु स्वयं अपने सहयोगियो के विरोध के कारण यू पी ए सरकार को इस विधेयक को उठाकर पीछे रख देना पड़ा। संचालन समिति की फिर बैठक होगी और भावी कार्रवाई के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

सधन्यवाद

आपका साथी

**(पी अभिमन्यु)**
**जनरल सेक्रेट्री**